



पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024

प्रलम्ब के लिये:

पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, [वायु गुणवत्ता](#), [उत्सर्जन और जैवविविधता संरक्षण](#), जलवायु परिवर्तन श्रेणी, वर्ष 2070 तक [शुद्ध-शून्य उत्सर्जन](#), अतिरिक्त कार्बन सिक, [भारत के वन](#), [आर्द्रभूमि](#), [कृषि-जैव विविधता](#), [मृदा स्वास्थ्य](#), [खाद्य हानि](#)।

मेन्स के लिये:

पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 का महत्त्व।

स्रोत: पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक

चर्चा में क्यों?

येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क ने वर्ष 2024 के लिये [पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक](#) (Environmental Performance Index- EPI) जारी किया।

EPI 2024 की मुख्य वशिषताएँ क्या हैं?

- वैश्विक परिदृश्य: एस्टोनिया वर्ष 1990 के स्तर से अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 59% की कमी लाकर सूचकांक में शीर्ष पर है।
 - रिपोर्ट से पता चलता है कि केवल पाँच देशों एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, तमोर-लेस्ते और यूनाइटेड किंगडम ने वर्ष 2050 तक नेट जीरो तक पहुँचने के लिये आवश्यक दर पर अपने GHG उत्सर्जन में कटौती की है।
 - इसके विपरीत उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया, मूल्यांकन किये गए आठ क्षेत्रों में सबसे नचिले स्थान पर हैं।
 - यूनाइटेड किंगडम के अलावा वर्ष 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (Environmental Performance Index- EPI) रिपोर्ट में पहचाने गए सभी देश वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के ट्रैक पर हैं और या तो धीमी प्रगति देखी गई है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, या उनका उत्सर्जन अभी भी बढ़ रहा है, जैसा कि चीन, भारत तथा रूस में देखा गया है।
- भारत का प्रदर्शन: भारत 27.6 अंकों के साथ 180 देशों में 176वें स्थान पर है, जो केवल पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्याँमार से ऊपर है।
 - वायु गुणवत्ता, उत्सर्जन और जैवविविधता संरक्षण के मामले में इसका प्रदर्शन खराब है, जिसका मुख्य कारण कोयले पर इसकी भारी निर्भरता है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तथा वायु प्रदूषण के स्तर में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
 - वशिष रूप से भारत वायु गुणवत्ता में 177वें स्थान पर है तथा वर्ष 2025 तक अनुमानित उत्सर्जन में 172वें स्थान पर होगा।
- सीमापार प्रदूषण का सबसे बड़ा उत्सर्जक: दक्षिणी एशिया में, भारत को सीमापार प्रदूषण के सबसे बड़े उत्सर्जक के रूप में पहचाना जाता है, जिसका असर पड़ोसी बांग्लादेश पर पड़ता है और वहाँ के नविसियों की खुशहाली पर भी असर पड़ता है।
 - अपनी नमिन समग्र रैंकिंग के बावजूद, नवीकरणीय ऊर्जा में नविश और वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतबिद्धता के कारण, भारत जलवायु परिवर्तन श्रेणी में अपेक्षाकृत बेहतर (133वें स्थान पर) है।
 - हालाँकि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये जलवायु परिवर्तन शमन नविश में प्रतविर्ष अतिरिक्त 160 बलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी।
- नए मेट्रिक्स प्रस्तुत किये गए: वर्ष 2024 EPI संरक्षित क्षेत्रों की प्रभावशीलता और कठोरता को मापने के लिये पायलट संकेतक प्रस्तुत करता है।

RANK	COUNTRY	SCORE
1	Estonia	75.3
2	Luxembourg	75.0
3	Germany	74.6
4	Finland	73.7
5	United Kingdom	72.7
6	Sweden	70.5
7	Norway	70.0
8	Austria	69.0
9	Switzerland	68.0
10	Denmark	67.9

//

176	India	27.6
177	Myanmar	26.9
178	Laos	26.1
179	Pakistan	25.5
180	Viet Nam	24.5

EPI पर भारत की प्रतिक्रिया क्या है?

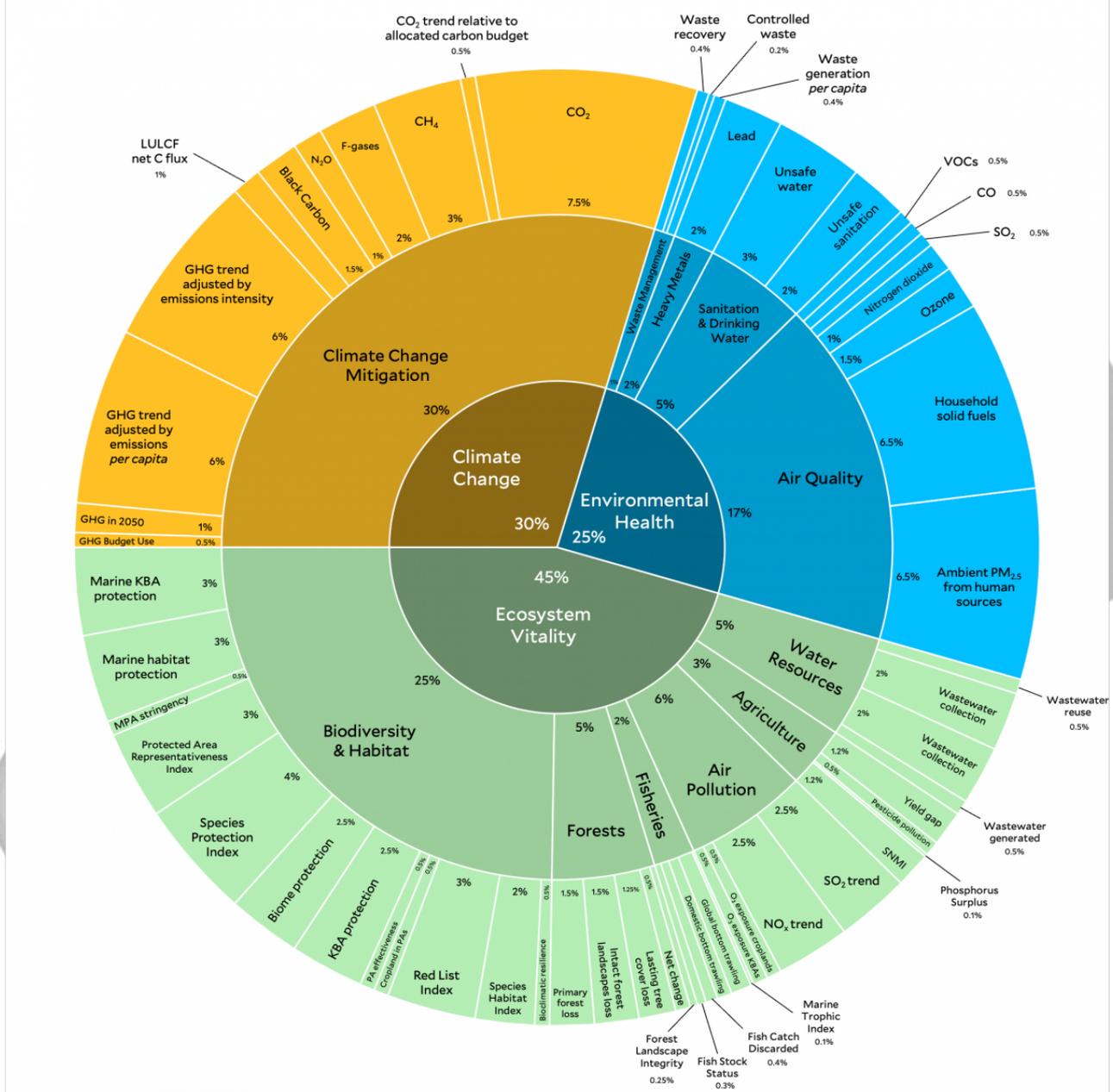
- अनुमानित GHG उत्सर्जन गणना: भारत का तर्क है कि गणना में लंबी अवधि (10 से 20 वर्ष), [नवीकरणीय ऊर्जा](#) क्षमता एवं उसका उपयोग, [अतिरिक्त कार्बन सिकि](#) तथा संबंधित देशों द्वारा कार्यान्वित [ऊर्जा दक्षता](#) उपायों को ध्यान में रखा जाना चाहिये।
 - वर्ष 2050 तक अनुमानित GHG उत्सर्जन की गणना पछिले 10 वर्षों में उत्सर्जन में परिवर्तन की औसत दर पर आधारित है, जैसा भारत अपर्याप्त मानता है।
- कार्बन सिकि बहिष्करण: EPI 2024 में वर्ष 2050 तक अनुमानित GHG उत्सर्जन प्रक्षेपवक्र की गणना में भारत के महत्वपूर्ण कार्बन सिकि, [आर्द्रभूमि एवं वनों](#) को शामिल नहीं किया गया है।
- पारस्थितिकी तंत्र की स्थितिकी अनदेखी: जबकि सूचकांक पारस्थितिकी तंत्र की सीमा की गणना करता है, यह उनकी स्थितिया उत्पादकता का मूल्यांकन नहीं करता है।
- प्रासंगिक संकेतकों का अभाव: सूचकांक में [कृषि-जैवविविधता](#), [मृदा स्वास्थ्य](#), [खाद्य हानि एवं अपशिष्ट](#) जैसे संकेतक शामिल नहीं हैं, जो अधिक कृषिआबादी वाले विकासशील देशों के लिये महत्वपूर्ण हैं।

पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक क्या है?

- परिचय: [पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक](#) (EPI) एक [द्विवार्षिक](#) सूचकांक है, जैसा सर्वप्रथम वर्ष 2002 में विश्व आर्थिक

मंच द्वारा [पर्यावरण स्थिरता सूचकांक \(ESI\)](#) के नाम से शुरू किया गया था।

- **मूल्यांकन लक्ष्य:** यह [संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों](#), [पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते \(2015\)](#) एवं [कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क](#) जैसे अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण नीति लक्ष्यों को पूरा करने के लिये देशों के प्रयासों का मूल्यांकन करता है।
- **फ्रेमवर्क:** EPI 2024, 3 नीतिगत उद्देश्यों के साथ **11 श्रेणियों** में समूहीकृत **58 प्रदर्शन संकेतकों** का लाभ उठाता है:
 - पर्यावरणीय स्वास्थ्य
 - पारस्थितिकी तंत्र जीवन शक्ति
 - जलवायु परिवर्तन
- EPI टीम पर्यावरणीय आँकड़ों से **0 से 100 तक के संकेतक** बनाती है, जो उच्चतम एवं न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले देशों को दर्शाते हैं।



EPI का महत्त्व क्या है?

- अंतरराष्ट्रीय सहयोग: EPI पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित एवं न्यायसंगत भवषिय की दशा में सामूहिक प्रयास को बढ़ावा देते हुए, अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा ज्ञान साझा करने को प्रोत्साहित करता है।
- सुशासन: EPI में वर्णित मज़बूत शासन ढाँचे, जैसे [पारदर्शिता, जवाबदेही के साथ-साथ प्रभावी नीति निर्माण](#), पर्यावरणीय नियमों एवं नीतियों को बढ़ावा देने और लागू करने के लिये आवश्यक हैं।
- वित्तीय संसाधन: पर्याप्त वित्तीय संसाधन पर्यावरणीय पहलों को लागू करने और साथ ही उन्हें बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे देशों को सतत विकास और बुनियादी ढाँचे में निवेश करने हेतु सक्षम बनाया जाता है।
- मानव विकास: [शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल](#) के साथ-साथ [समग्र कल्याण](#) जैसे कारकों सहित मानव विकास के उच्च स्तर वाले देश पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं और प्रभावी उपायों को लागू कर सकते हैं।
- नियामक गुणवत्ता: प्रभावी प्रवर्तन तंत्र के साथ मज़बूत और अच्छी तरह से डिज़ाइन किये गए पर्यावरण वनियम, पर्यावरणीय गतिवट को कम

करने तथा स्थायित्व मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

EPI से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- माप जटिलताएँ: इसमें शामिल जटिल गतिशीलता के साथ सभी क्षेत्रों में मानकीकृत पद्धतियों की कमी के कारण जैवविविधता हानि या पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य को मापना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- डेटा की उपलब्धता एवं विश्वसनीयता: कुछ विकासशील देशों में मज़बूत नगिरानी प्रणालियों की कमी हो सकती है अथवा व्यापक पर्यावरणीय आँकड़े एकत्रित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परिणामस्वरूप अपूर्ण छवि प्राप्त हो सकती है।
- राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में संतुलन: देश पर्यावरण संरक्षण की अपेक्षा आर्थिक विकास को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप EPI अनुशासकों के क्रियान्वयन में संभावित संघर्ष या प्रतिरोध उत्पन्न हो सकता है।
 - संसाधन नष्टिकरण या जीवाश्म ईंधन आधारित उद्योगों पर अत्यधिक निर्भर देशों को अधिक सतत प्रथाओं को अपनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- वित्तपोषण और संसाधन संबंधी बाधाएँ: विकासशील देशों को पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिये पर्याप्त धनराशि या विशेषज्ञता आवंटित करने में कठिनाई हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रगति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। हालाँकि विकसित देशों ने विकासशील देशों के शमन के लिये पर्याप्त धनराशि आवंटित नहीं की है।
- सीमा पार पर्यावरणीय प्रभाव: वायु प्रदूषण, जल प्रबंधन या वन्यजीव संरक्षण जैसे सीमा पार मुद्दों के समाधान के लिये बहुपक्षीय समझौतों और संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता हो सकती है।

भारत में पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम क्या हैं?

- जलवायु परिवर्तन: [जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना](#)
- मरुस्थलीकरण: [मरुस्थलीकरण से निपटने के लिये राष्ट्रीय कार्य कार्यक्रम](#)
- प्रदूषण नियंत्रण: [राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम](#)
- पर्यावरण प्रभाव आकलन: [पर्यावरण प्रबंधन योजना](#)
- वन संरक्षण: [राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम](#)
- प्रजाति संरक्षण: [प्रोजेक्ट एलीफेंट](#), [प्रोजेक्ट टाइगर](#)

आगे की राह

- बेहतर कार्यप्रणाली और कार्बन सिक लाना: वगित 10 वर्षों में परिवर्तन की औसत दर पर पूर्ण रूप से निर्भर रहने के बजाय, अनुमानित GHG उत्सर्जन प्रक्षेप पथ की गणना करने के लिये एक लंबी समय-सीमा (जैसे- 20-30 वर्ष) को शामिल करना।
 - [प्रतिप्रकार वनरोपण नधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण \(CAMPA\)](#) जैसी पहलों के माध्यम से कार्बन पृथक्करण को बढ़ाने के प्रयासों को मान्यता दी जानी चाहिये।
- संकेतकों के समूह का विस्तार करना: ऐसे संकेतक शामिल करना, जो बड़ी कृषि आबादी वाले विकासशील देशों के लिये प्रासंगिक हों, जैसे कृषि-जैवविविधता, मृदा स्वास्थ्य, खाद्य हानि और अपशिष्ट प्रबंधन।
 - भारत के लिये, EPI में जैविक खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, फसल विधीकरण और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के उपायों जैसे संकेतक शामिल किये जा सकते हैं, जो सतत कृषि की दिशा में देश के प्रयासों को दर्शाते हैं।
- संकेतकों के भार सहित वित्तपोषण में पारदर्शिता: इसके संकेतकों के भार में किसी भी परिवर्तन हेतु स्पष्ट एवं पारदर्शी स्पष्टीकरण प्रदान करने के साथ भारत जैसे देशों द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान करने पर ध्यान देना चाहिये।
 - सरकारी प्रतिनिधियों एवं विशेषज्ञों सहित हितधारकों के बीच परामर्श पर बल दिया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संकेतकों का भार वैश्विक प्राथमिकताओं एवं राष्ट्रीय संदर्भों के साथ समन्वित हो।

?????? ???? ????;

पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI), 2024 के प्रमुख नष्टिकरणों पर चर्चा कीजिये। इसके अनुसार नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में से संबंधित कौन-सी वैश्विक चुनौतियाँ वदियमान हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सा/से भारत सरकार के 'हरति भारत मशिन' के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है/हैं? (2016)

- 1- पर्यावरणीय लाभों एवं लागतों को केंद्र एवं राज्य के बजट में सम्मिलित करते हुए 'हरति लेखाकरण (ग्रीन अकाउंटिंग)' को अमल में लाना ।
- 2- कृषि उत्पाद के संवर्द्धन हेतु द्वितीय हरति क्रांति आरंभ करना जिससे भविष्य में सभी के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो ।
- 3- वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्द्धन करना तथा अनुकूलन एवं न्यूनीकरण के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

प्रश्न. 'भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि (ग्लोबल क्लाइमेट, चेंज एलायंस)' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

- 1- यह यूरोपीय संघ की पहल है ।
- 2- यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।
- 3- इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान (WRI) और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद् (WBCSD) द्वारा किया जाता है ।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

??????:

प्रश्न.1 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये । इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं? (2021)